

वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त
जलागम विकास

संख्या ५५ / एस०ओ०एफ०आ०डी०सी०/जलागम
देहरादून दिनांक मार्च १७, २००१

कार्यालय ज्ञाप

जलागम विकास परियोजनाओं में समन्वय, अनुश्रवण एवं परियोजना निर्माण के लिए अन्तर विभागीय टास्कफोर्स के गठन विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जलागम विकास हेतु आलू यंचवर्णीय योजना में केन्द्र सरकार के स्तर पर पर्याप्त धनराशि का प्राविधान किया गया है। अतः केन्द्र सहायिता परियोजनाओं के माध्यम से उत्तरांचल राज्य में जलागम विकास को काफी गति प्रदान की जा सकती है।

2. वर्तमान में जलागम विकास का कार्य प्रदेश में विभिन्न विभागों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से कृषि, भूमि एवं बस संरक्षण, ग्राम्य विकास एवं वन विभाग सम्मिलित है किन्तु वर्तमान में विभागों में राज्य स्तर पर समन्वय का अभाव है। अतः सभी सम्बन्धित विभागों में घनिष्ठ समन्वय स्थापित करने के ल्दूरेश्वर से एक अन्तर विभागीय टास्क फोर्स का गठन निम्नानुसार किया जाता है :—

(I)	सचिव जलागम एवं कृषि/ मुख्य परियोजना निदेशक आईएम्ब्लूडी०पी०	अध्यक्ष
(II)	परियोजना निदेशक आईएम्ब्लूडी०पी० शिवालिक	सदस्य
(III)	अपर कृषि निदेशक	सदस्य
(IV)	मुख्य वन संरक्षक आण्वी०पी०	सदस्य
(V)	स्टाफ ऑफिसर एफ०आ०डी०सी०/ संयुक्त सचिव (जलागम)	सदस्य
(VI)	अपर सचिव वन/ प्रभारी भूमि संरक्षण निदेशालय	सदस्य सचिव

3. उपरोक्त टास्क फोर्स का मुख्य कार्य प्रदेश में संचालित जलागम विकास से संबंधित सभी परियोजनाओं जो जाहे किसी भी स्रोत से वित्त योगित की जा रही हो, में आवश्यक समन्वय स्थापित करना होगा। इस टास्क फोर्स का कार्यालय भूमि संरक्षण निदेशालय में स्थापित किया जायेगा और इस कार्यालय के संचालन हेतु सभी विभागों से प्रशासनिक एवं वित्तीय संसाधनों की पुरिंग की जायेगी।

4. इस टास्क फोर्स द्वारा वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा के अन्तर्गत सम्मिलित सभी विभागों द्वारा अब तक संचालित एवं वर्तमान में संचालित सभी जलागम विकास

परियोजनाओं के संबंध में जनपदवार, बाटरसोडवार, भाइकोशोडवार सूचना मानविक्र के साथ निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराई जायेगी एवं साथ ही साथ यह भी इंगित किया जायेगा कि वर्तमान में कहाँ गेप्स अवस्थित है। इस प्रकार वर्तमान में प्रदेश में जलागम विकास परियोजनाओं के संबंध में इस स्टेटस पेपर को बनाने का कार्य दिनांक 31 मार्च 2001 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

5. मुझे यह भी कहने का निरेश हुआ है कि भविष्य में किसी भी विभाग द्वारा जलागम विकास के संबंध में कोई भी परियोजना भिना इस नोट्स फोर्म के सालगति ने तित्ता पोषण हेतु केन्द्र सरकार अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं को प्रेक्षित नहीं की जायेगी।

6. केन्द्र सरकार द्वारा गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं को भी जलागम विकास हेतु कार्यवाही संस्थाओं के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। अर्थात् यह अविवाद होगा कि इस टास्क-फोर्म द्वारा ऐसे गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं को भी, जो जलागम विकास की परियोजना का कार्य कर रहे हों, उन्हें परियोजना को दैयार करने में यथा आवश्यक भवद की जाय एवं उन्हें वांछित सभी सूचनाएं उपलब्ध करा दी जायें। साथ ही गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए भी यह आवश्यक होगा कि वे अपनी परियोजनाओं को वित्त पोषण हेतु भेजने से पूर्व टास्क-फोर्म से सहमति प्राप्त कर लें।

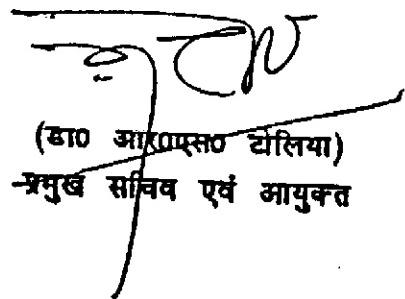
उक्त टास्क-फोर्म के कार्यों में गति प्रवान करने एवं उसे मार्ग दर्शन हेतु राज्य सर पर निम्नानुसार एक राज्य स्तरीय जलागम प्रबंध समिति का गठन किया जाता है:-

(I)	प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास	अध्यक्ष
(II)	सचिव वन	सदस्य
(III)	अपर सचिव कृषि	सदस्य
(IV)	अपर सचिव ग्राम्य विकास	सदस्य
(V)	अपर सचिव उद्यान	सदस्य
(VI)	गैर सरकारी स्वयं सेबी संस्थाओं के नामित प्रतिनिधि	सदस्य
(VII)	सचिव कृषि एवं जलागम/मुख्य परियोजना निदेशक - आईडब्लूडीपी०	सदस्य सचिव

उक्त समिति प्रत्येक त्रैमास में एक बार बैठक करेगी एवं प्रदेश में जलागम विकास के संबंध में नीति निर्धारण एवं जलागम विकास के कार्यों की समीक्षा का कार्य करेगी। इस समिति का मुख्य दायित्व यह होगा कि जलागम विकास हेतु ऐसी नीति निर्धारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय जिसमें सभी संबंधित विभागों के समन्वय के साथ-साथ ग्राम स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की भी अधिकाधिक भागेदारी सुनिश्चित की जा सके।

इसके साथ-साथ राज्य में जलागम विकास एवं ग्राम्य विकास विभाग द्वारा घलाये जा रहे स्वरोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यों का भी केन्द्राभिमुखीकरण (Convergence) आवश्यक है। इस स्तरीय जलागम विकास समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि जलागम विकास की परियोजनाओं के

साथ ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित विभागीय केन्द्र पोर्टफोलियो की किस प्रकार डिप्टीलिंग की जा सकती है एवं तदनुसार आय-व्यय में यथा आवश्यक राज्यांश का प्रावधान भी करा दिया जाय, जिससे प्रदेश में जलागम विकास हेतु अधिकाधिक केन्द्रीय सहायता प्रदेश को प्राप्त हो सके।

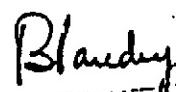

(डॉ जायशंकर भगत)
अमुख सचिव एवं आयुक्त

संख्या ५५ (१) / एस०ओ०एफ०आर०डी०सी०/जलागम तददिनांक

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. समस्त सदस्य टास्क-फोर्म
2. समस्त सदस्य राज्य स्तरीय जलागम प्रबंध समिति.
3. समस्त विभागध्यक्ष/ अपर निदेशक बन एवं ग्राम शाखा.
4. समस्त जिलाधिकारी.
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी.
6. स्टाफ ऑफिसर बन एवं ग्राम आयुक्त शाखा.

आज्ञा से,


(बौद्धीपी० पाण्डेय) १७/३/२००१
सचिव